बहादुरपुरा (नान्देड़) में ऐतिहासिक किला

6942. **श्री केशव राव धोंडगे :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य नान्देड जिले में बंधर तालुक के गाव बहादुरपुरा में एक ऐतिहासिक किला है ;

(ख) यदि हां, तो इसके रख-रखाव के लिए क्या प्रबन्ध किये गये है ;

(ग) क्या इस किले के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए जनता की ओर से इसकी मरम्मत और रख-रखाव की मांग की गई है, और

(घ) यदि हा, तो इस कार्य के लिए सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता प्रदान की गई है और यदि कोई सहायता नही दी गई है तो इस क्या कारण है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हा ।

(ख) इस किले का रख-रखाव महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया जा रहा है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार को जनता की ऐसी किसी मांग की जानकारी नही है ।

(घ) प्रश्न ही नही उठता ।

भूखमरी में हुई मौतें

6943. **श्री राम सेवक हजारी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भुखमरी से कितने व्यक्तियो की मृत्यु हुई ;

(ख) इनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए राज्यो को दी गई सहायता और परामर्श का ब्यौरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) (क) और (ख) अभी तक किसी भी राज्य सरकार से गत तीन वर्षों के दौरान भुखमरी से मौत की कोई सूचना प्राप्त नही हुई है ।

(ग) कृषि उत्पादन बढ़ाने व ग्रामीण रोजगार के सृजन के लिए विभिन्न स्कीमो के जरिए कार्यान्वित की जा रही सरकार की बुनियादी नीति के अलावा अभाव की स्थिति का सामना करने के लिए छठे वित्त आयोग की सिफारिशो के अनुसार राज्य सरकारो को मार्जन धनराशि दी गई है । इसके अतिरिक्त, प्रभावित क्षेत्रो मे उन लोगो को नि शुल्क राहत देने के लिए जिन्हें रोजगार नही दिया जा सकता, से संबंधित राज्य सरकारो के कार्यक्रमो की अनुपूर्ति के लिए, वर्तमान सरकार प्राकृतिक आपदाओ से प्रभावित राज्य सरकारों

को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान कर रही है। हाल ही में शुरू की गई एक अन्य महत्वपूर्ण स्कीम "कार्य के लिए खाद्य स्कीम" है जिसके अन्तर्गत भारत सरकार राज्य सरकारों को रोजगार बढ़ाने के लिए व मजदूरों को कम कीमतों पर अनाज की आपूर्ति करने के लिए खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराती है।

Memorandum by the Central Government Employees, Mukundnagar, Pune regarding sale of tenements to the occupants

6944. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether he has paid a visit to the Flood affected Central Government Servants' colony at Mukundnagar, at Pune (Maharashtra) in the first week of December, 1977 and the Chairman of the said colony had submitted a memorandum with regard to their demands of sale of Tenements to occupants;

(b) what action have Government taken in respect of the said memorandum; and

(c) if no action has so far been taken thereon, the reasons thereof?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) to (c). A letter dated 4th December, 1977 was received from the Association of Flood Affected Central Government Employees requesting for the relaxation in the terms of sale of quarters. The decision to sell the quarters at Mukundnagar, Pune to the original occupants was taken as a special case and the terms of sale of those quarters have already been decided. It is not possible to relax the terms of sale.

Basic Amenities in new colonies in Delhi

6945. SHRI RAJ KESHAR SINGH: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn towards news item entitled 'Action threat by new colonies' published in the 'National Herald' dated 25th March, 1978;

(b) if so, reaction of the Government thereto; and

(c) steps taken or being taken by the DDA to provide civic amenities and other services in the new colonies?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) to (c). Yes, Sir. Civic amenities like street lighting, drinking water, community latrines, roads and streets have already been provided in all the Resettlement Colonies. Tented schools are being replaced by pucca buildings and in some of the colonies buildings have already come up. Land has already been allotted to the Delhi State Industrial Development Corporation in many Resettlement colonies for construction of community industrial sheds. The existing J. J. Resettlement colonies have been transferred to the Municipal Corporation of Delhi.

निर्माण और आवास मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति

6946. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया गया है; और